P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-VII* March-2016

वर्तमान दशक में भारतीय खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (F.D.I.) का विश्लेषण

राहुल श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज,
गोरखपुर

सारांश

21वीं सदी में भारत की पहचान एशिया की दूसरी तेजी से उभरती हुयी अर्थव्यवस्था (राष्ट्र) के रूप में होने लगी। इसका मुख्य कारण पिछले दशक में अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर आठ प्रतिशत की प्राप्ति है। परन्तु वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में घरेलू आर्थिक संकेतों को देखे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। मिड ईयर इक्नोमिक एनेलिसिस–2014–15,मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार,**''भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की त्रयमासिक वृद्धिदर 5.5 प्रतिशत रही।''**घरेलू स्तर पर वर्तमान सरकार के समक्ष वस्तु और सेवा कर (जी0एस0टी0), भूमि अधिग्रहण बिल, खाद्य महंगाई दर इत्यादि समस्याएँ चुनौती बनकर आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में बाधक बनी हुयी हैं। वहीं दूसरी तरफ वैष्विक स्तर पर ग्रीस आर्थिक संकट, तेज कीमतों में अस्थिरता, सीमा विवाद इत्यादि ऐसी समस्याएँ हैं, जो अर्थव्यवस्था की रफतार को धीमा कर रही है। इन घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत सरकार पिछले एक दशक में भारतीय खुदरा बाजार ने प्रत्यक्ष विदशी निवेश (एफ0डी0आई0) का सकारात्मक संकेतों को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्य शब्दः एफ0डी0आई0, खुदरा बाजार, आर्थिक सुधार,सकारात्मक संकेत, विकास।

प्रस्तावना

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में खुदरा बाजार क्षेत्र आज दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहाँ रोजगार के सर्वाधिक अवसरों का सृजन हो रहा है। वर्ष 2010 में इस बाजार का आकार 353 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो वर्ष–2014 में बढ़कर 543 बिलियम अमरिकी डालर हो गया। (सोत–आई0बी0ई0एफ0) पिछले एक दशक में तो जैसे इस क्षेत्र में क्रान्ति आ गयी है। इस क्षेत्र को अपार संभावनाओं के कारण देश और विदेशों के उद्योगपति देश में निवेश और उत्पादन करने के अवसर में है। ग्लोबल रिटेल डेवलपमेन्ट इन्डैक्स–2012 के अनुसार भारतीय खुदरा बाजार विश्व के 30 तेजी से उभरते हुए राष्ट्रो में पाँचवां स्थान रखता है। इस इन्डेक्स से यह भी पता चलता है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वालो अर्थव्यवस्था, सर्वाधिक युवाजन शक्ति (18–59 वर्ष) वाला देश एवं सर्वाधिक नवीन उत्पादनों को ग्रहण करने वाला देश है।उक्त कारणों से भारत के विदेशी खुदरा बाजार में विश्व के विभिन्न बहुराष्ट्रोय कम्पनियाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं।

भारत सरकार के द्वारा पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिये हैं। जैसे–100 प्रतिशत एफ0डो0आई0 इन सिंगल ब्राण्ड, 51 प्रतिशत एफ0डी0आई0 इन मल्टी ब्राण्ड, 51 प्रतिशत एफ0डी0आई0 इन डिफेन्स सेक्टर। वर्ष–2014 में चुनी गयी नयी सरकार ने अपने पहले बजट में 'उदारीकृत प्रत्यक्ष विदशी निवेश' का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वकांक्षी परियोजना **''मेक इन इण्डिया''** भी एक प्रोत्साहक कदम हैं, जिसके द्वारा खुदरा बाजार में निवेश के लिए उचित वातावरण तैयार होगा।

साहित्य अवलोकन

पिछले एक दशक में भारतीय खुदरा बाजार संगठित रूप से औसतन 25–30 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 10 प्रतिशत है और कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने वाला क्षेत्र है। (ए–गुप्ता, 2010) जान लेंगलेसल्स थर्ड एनूअल रिटेलर सेंटिमन्ट सर्वे–एशिया के अनुसार–भारत में

संगठित खुदरा बाजार का विकास जैसे–होलसेल कैस एण्ड कैरी स्टोर की वृद्धि दर 150 प्रतिशत, सुपर मार्केट 100 प्रतिशत और हाईपर मार्केट की वृद्धि 70–80 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। गोल्डमैन साच के अनुसार– भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धिदर 2015 में चीन से आगे हो जायेगी। (स0टी0 केयरने 2009)

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र का विषय भारतीय खुदरा बाजार में एफ0डी0आई0 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इस सम्बन्ध में शोध–पत्र के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

1. वर्तमान समय मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि दर का क्षेत्रवार विश्लेषण करना।
2. भारतोय खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तरीकों का विश्लेषण।
3. भारतीय खुदरा बाजार के संगठित और असंगठित क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवश का विश्लेषण।
4. शोध–पत्र के अन्त में शोध के उददेश्यों के अनुसार सुझाव व निष्कर्ष देना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र का विषय मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक है, जो विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी सूचनाओं पर आधारित है। इसके अन्तर्गत द्वितीयक आँकड़े, पुस्तक एवं न्यूज पेपर, जनरल इत्यादि का प्रयोग अध्ययन की आवश्यकतानुसार किया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ विदेशों से पूँजी का अर्न्तप्रवाह है। यह एक दीर्घकालीक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विदेशी निवेशक अन्य देशों की कम्पनियों के प्रबन्धन में नियंत्रण स्थापित कर उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अर्न्तराष्ट्रीय मुद्राकोश और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने एफ0डी0आई0 को **'क्रास बार्डर इन्वेस्टमेन्ट'** के रूप में परिभाषित किया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दो तरीके (रूट) हैं–

1. आटोमैटिक रूट
2. गवर्नमेन्ट रूट

आटोमैटिक रूट द्वारा एफ0डी0आई0 के नियम व शर्त भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एफ0डी0आई0 नीति में दिय जाते हैं। सरकार इन नियमों व शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन करती रहती है, जबकि गवर्नमेन्ट रूट द्वारा एफ0डी0आई0 के लिए फारेन इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन बोर्ड से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इसमें डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेन्स की महत्वपूर्ण भूमिका हाती है। अध्ययन के सुविधा हेतु वर्ष 2000 से 2014 के बीच भारत में एफ0डी0आई0 का क्षेत्रवार विश्लेषण तालिका नं0–1 से स्पष्ट किया गया है।

भारत में एफ0 डी0 आई0 का अर्न्त–प्रवाह (अप्रैल–2000 से जुलाई 2014)

तालिका–1

क्र. सं.	क्षेत्र	एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह की धनराशि (करोड़ रूपये में)	कुल एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह का प्रतिशत
1	सर्विस सेक्टर	191752.15	17.73
2	कन्स्ट्रक्शन डेवलपमेन्ट	111127.49	10.40
3	टेलिकम्प्यूनिकेशन	8060847	7.23
4	कम्प्यूटर साफ्टवेयर एण्ड हार्डवेयर	61707.07	5.76
5	ड्रग एण्ड फार्मास्यूटीकल्स	31340.03	5.47
6	आटो मोबिल इण्डस्ट्रीज	49678.09	4.41
7	कैमिकल	47538.99	4.40
8	पावर	44667.08	4.05
9	मेटालाजिकल इण्डस्ट्रीज	39225.17	3.61
10	होटल एण्ड टूरिज्म	38030.37	3.25
11	पेट्रोलियम एण्ड नैचूरल गैस	31501.55	2.84
12	फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज	34719.02	2.61
13	ट्रेडिंग	29742.99	2.53
14	इन्फार्मेसन एण्ड ब्राड कास्टिंग	18189.01	1.64
15	इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट	17792.64	1.62
16	नान–कन्वेक्सनल एनर्जी	17053.31	1.44
17	इण्डस्ट्रीयल मशिनरी	15490.15	1.33
18	सिमेन्ट एण्ड जिप्सन प्रोडक्ट	13446.47	1.27
19	कन्सलटेन्सी सर्विस	13148.03	1.17
20	मिस मैकेनिकल एण्ड इन्जीनियरिंग गुड्स	12413.44	1.15
21	कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी	12953.51	1.15
22	हास्पिटल एण्ड डाइगोनोस्टिक सेन्टर	12413.57	1.07
23	फार्मनटेशन इण्डस्ट्रीज	10591.66	0.88
24	एग्रिकल्चर सर्विस	8517.34	0.76

25	पोर्टस	6719.33	0.72
26	रबर गुड्स	8826.68	0.71
27	टैक्स टाईल्स	7058.86	0.64
28	इलेक्ट्रानिक्स	6337.12	0.59
29	सी–ट्रान्सपोर्ट	6120.34	0.57
30	प्राइम मोवर	5890.88	0.50
31	माइनिंग	4651.50	0.46
32	एजूकेशन	4961.76	0.42
33	पेपर एण्ड पल्प्स	4235.30	0.39
34	मेडिकल एण्ड सर्जिकल अप्लाइन्सेज	4467.39	0.38
35	सोप्स, कास्मेटिक्स, ट्वाइलेट पेपर	4175.86	0.35
36	मशीन टूल्स	3407.95	0.30
37	सिरेमिक्स	3115.31	0.29
38	रेलवे रिलेटेड कम्पोनेन्ट्स	3393.95	0.28
39	एयर ट्रान्सपोर्ट्स	2348.12	0.22
40	डायमण्ड, गोल्ड आर्नामेन्ट्स	2185.63	0.20
41	ग्लासेज	2207.85	0.19
42	वेजिटेबल आयल एण्ड वनस्पति	2095.22	0.18
43	प्रिण्टिंग ऑफ बुक्स	2138.83	0.18
44	एग्रिकल्वलर मशीनरी	1821.57	0.16
45	फर्टिलाइजर्स	1543.76	0.14
46	कैमिकल, आफिस एण्ड हाउस होल्ड इक्विटमेन्ट	1420.20	0.13

स्रोत–डिपार्टमेन्ट ऑफ इण्डस्ट्रियल पालिसी एण्ड प्रमोशन ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री।

तालिका–01 से स्पष्ट है कि वर्ष–2000 से 2014 के बीच सर्वाधिक एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह सेवा क्षेत्र में 191752.15 करोड़ रूपये का हुआ, जा कुल एफ0डी0आई0 का 17.73 प्रतिशत है। जबकि सबस कम एफ0डी0आई0 कामर्शियल, आफिस और हाउस होल्ड इक्विकमेन्ट में 1420.20 करोड़ रूपये का है, जो कुल एफ0डी0आई0 का 0.13 प्रतिशत है। इसी प्रकार से कन्स्ट्रक्शन डवलपमेन्ट, टेली कम्प्यूनिकेशन, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एण्ड हाडवेयर, ड्रग एण्ड फार्मास्यूटीकल्स क्रमशः 02, 03, 04 आर 05वां सर्वाधिक एफ0डी0आई0 प्राप्त करने वाले क्षेत्र है।

भारत में एफ0डी0आई0 की वृद्धि दर (वर्ष–2000 से 2010 के बीच) के बीच

तालिका–2

वर्ष	एफ0डी0आई0 का अर्न्तप्रवाह(करोड़ रूपये में)	वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
2000 -01	4029	87
2001 - 02	6130	52
2002 -03	5035	&17
2003-04	4322	&14
2004-05	6051	40
2005-06	8961	48
2006-07	22826	155
2007-08	34835	52
2008-09	35180	1
2009-10	37182	5

स्रोत–एफ0डी0आई0 स्टेटिस्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड कामर्स एस साइटेड इन अनिथा एण्ड डा0 के0 मारन (2011)

भारत में एफ0डी0आई0 की वृद्धि दर की प्रतिशत वृद्धि

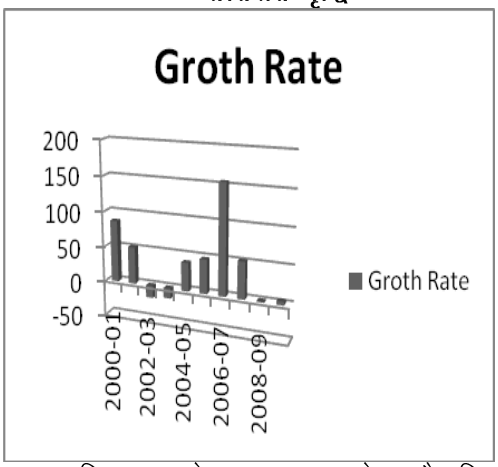

तालिका–2 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 से लेकर 2009–10 तक एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह में उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। वर्श–2002–03 व वर्ष 3003–04 में वार्षिक वृद्धि दर –17 प्रतिशत एवं –14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी, जिसका मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मन्दी था। जबकि अन्य वर्षों में भारत में एफ0डी0आई0 का अर्न्तप्रवाह धनात्मक ही रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2014–15 के

अनुसार **''सरकार अपने बजट वर्ष 2014–15 में एफ0डी0आई0 पालिसी को 'इन्वेस्टर फ्रैण्डली' बनाने के साथ आटोमैटिक रूट से विभिन्न क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ0डी0आई0 की घोषणा की है।'' साथ ही खुदरा बाजार में एफ0डी0आई0 को बढ़ाने के लिए 'उदारीकृत एफ0डी0आई0 नीति' का निर्माण कर इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने के उपाय किये गये हैं। गवर्मेन्ट रूट से रक्षा क्षेत्र में 49 पतिशत एफ0डी0आई0 करने का प्रावधान की बात कही गयी है। बजट में रेलवे के आधारभूत संरचना के निर्माण, रख–रखाव, निर्माण व संचालन में एफ0डी0आई0 को आटोमैटिक रूप से 100 प्रतिशत करने की घोषणा की गयी है।''** भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष–2014–15 में इस बात की सूचना भी दी गयी कि नवम्बर 2014–15 के बीच कुल एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह 27.4 बिलियन अमेरिकी डालर पर हुआ। जबकि संचयी एफ0डी0आई0 अर्न्तप्रवाह अप्रैल 2000 से नवम्बर 2014 के बीच कुल 250.9 बिलियन अमेरिकी डालर का हुआ।(स्रोत–बजट–2014–15, भारत सरकार–2014) भारत में सर्वाधिक एफ0डी0आई0 करने वाले विश्व के पाँच प्रमुख देश क्रमशः –मौरिसस (37 प्रतिशत), सिंगापुर (11 प्रतिशत), यू0के0 (10 प्रतिशत), जापान (7 प्रतिशत), यू0एस0ए0 (6 प्रतिशत) हैं। इन देशों द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 के बीच लगभग 320092 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया। (स्रोत–डिपार्टमेन्ट ऑफ इण्डस्ट्रियल पालिसी एण्ड प्रमोशन : गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया)

प्रस्तुत शोध–पत्र का एक मुख्य उद्देश्य भारतीय खुदरा बाजार में एफ0डी0आई0 के तरीकों का विश्लेषण करना है। भारतीय खुदरा बाजार का इतिहास प्राचीन कालीन है। प्राचीन काल में **'साप्ताहिक बाजार'** के रूप में क्रेता–विक्रेता वस्तुओं का आदान–प्रदान करते थें। यह परम्परा आज भी **'बनिये की दुकान'** के रूप में हमारे समाज में प्रचलित है। भारत में खुदरा बाजार दो वर्गो में बँटा है–

1. संगठित खुदरा बाजार
2. असंगठित खुदरा बाजार

संगठित खुदरा बाजार का अर्थ ऐसे व्यापार से है, जिन्हें बिक्री कर व आयकर विभाग से लाइसेन्स अथवा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। ये मुख्यतः निजी अधिकार के फुटकर व्यापारी होते हैं। जबकि असंगठित खुदरा बाजार का अर्थ कम लागत वाली परम्परागत व्यापारी होते हैं, जैसे–स्थानीय दुकानदार, जनरल स्टोर, पान–बीड़ी की दुकान, मिठाई की दुकान एवं हाथों से बनायी जाने वाली वस्तुओं की दुकान इत्यादि शामिल किये जाते हैं। डौलटी (2011) के अनुसार **''विकसित देशों जहाँ 80 प्रतिशत संगठित खुदरा बाजार हैं, वहीं भारत में संगठित खुदरा बाजार का हिस्सा केवल 05 प्रतिशत है।''** यही बात भारत के पक्ष में जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार व उत्पादन में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं के गुणवत्ता व उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। **''एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खुदरा बाजार का हिस्सा 14 से 15 प्रतिशत होगा। भारत में लगभग 1.2 बिलियन उपभोक्ता हैं। जबकि देश में केवल 4 प्रतिशत व्यवसायिक स्टोर व सुपर बाजार हैं।''**[2] नीचे दिये गये तालिका नं0–3 में संगठित एवं असंगठित खुदरा बाजार की हिस्सेदारी को स्पश्ट किया गया है–

तालिका–3
भारतीय खुदरा बाजार (असंगठित और संगठित) का प्रतिशत

वर्ष	संगठित (प्रतिशत)	असंगठित(प्रतिशत)
2005	3-6	96-4
2007	4-1	95-8
2010	5-0	95-0
2012	8-0	92-0
2015 (E)	21-0	79-0
2020 (E)	24-0	76-0

E-Expected (प्रत्याशित)

सोत

1. डौलटी (2011),''इण्डियन रिटेल मार्केटः इनबेरिसिंग ए न्यू ट्रेजेक्टरी'', सितम्बर –2005 –2015
2. फिक्की (2011) ''सेक्टर प्रोफाइल, 02 दिसम्बर, 2010–20.

भारतीय खुदरा बाजार (असंगठित और संगठित) का प्रतिशत

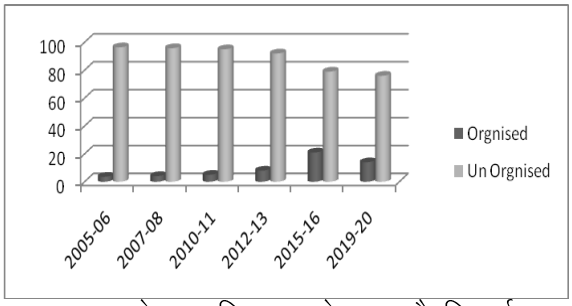

उपरोक्त तालिका–3 से स्पष्ट है कि वर्ष–2005 से 2010 तक संगठित खुदरा बाजार में वृद्धि बहुत अनुकुल नहीं रही। इस अवधि में तुलनात्मक रूप से वृद्धि दर क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 21.9 प्रतिशत रही। परन्तु वर्ष–2010 के उपरान्त वृद्धि दर 60 प्रतिशत की रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना था। एसा अनुमान है कि वर्ष–2012 से 15 के बीच इसमें वृद्धि दर 2.6 गुना से अधिक की होगी। जबकि वर्ष–2020 तक इस क्षेत्र की वृद्धि दर 7 प्रतिशत ही होगो और बाजार का आकार 850 बिलियन यू0एस0 डालर के बराबर होगा। अनुमान यह भी है कि वर्ष–2025 तक संगठित खुदरा बाजार के वृद्धि दर 25 प्रतिशत और संगठित खुदरा बाजार की वृद्धि दर 5 प्रतिशत होगी। (स्रोत–फिक्की (वर्श–2011) ''सेक्टर प्रोफाइल सितम्बर 2010–20'')

अध्ययन की सुविधा हेतु खुदरा बाजार क्षेत्र में सरकार के द्वारा समय–समय पर किये गये नीतिगत परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। इस विवरण में वर्ष और उससे सम्बन्धित नीतियों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे– **1997 से वर्ष 2005** के बीच कैश एण्ड कैरी विधि द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रावधान, **वर्ष–2006 से वर्ष 2010** के बीच सिंगल ब्राण्ड रिटेल के अन्तर्गत सरकार के अनुमति

से इस क्षेत्र में 51 प्रतिशत का एफ0डी0आई0 तथा 100 प्रतिशत एफ0डी0आई0 सिगल ब्राण्ड रिटेल में एवं 51 प्रतिशत एफ0डी0आई0 मल्टी ब्राण्ड रिटेल में निवेश की सुविधा प्रधान की गई। **वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013** के बाद सरकार ने 30 प्रतिशत उत्पाद स्रात को स्थानीय स्तर पर लेने की शर्त को हटा लिया।

इन उपायों का ही यह परिणाम है कि भारतीय खुदरा बाजार वर्ष–2020 तक बढ़कर 650 बिलियन यू0एस0 डालर होने का अनुमान है। वर्तमान समय में कैस एण्ड कैरी तथा सिंगल ब्राण्ड तरीक से विश्वभर के निवेशक/उत्पादक इस क्षेत्र म 100 प्रतिशत उत्तराधिकार के साथ व्यापार कर रहे हैं। जैसे– वाल्मार्ट और मैट्रो।

अध्ययन की आवश्यकतानुसार भारत में संगठित और असंगठित खुदरा बाजार क्षेत्र के अन्तर को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

संगठित और असंगठित खुदरा बाजार में अन्तर

तालिका–4

क्र. सं.	मापदण्ड	संगठित खुदरा बाजार	असंगठित खुदरा बाजार
1	उत्तराधिकार	बड़े उद्योग घराने	पारिवारिक उद्योग
2	आकार	तुलनात्मक रूप से बड़े स्टोर	छोटे स्टोर
3	बिक्री मूल्य	एम0आर0पी0 से कम	एम0 आर0 पी0 के बराबर
4	रोजगार प्रकृति	बाहर से नियोजित कर्मचारी	पारिवारिक सदस्य
5	स्टोर की स्थिति	व्यवस्थित	अव्यवस्थित
6	वस्तुओं की उपलब्धता	ब्राण्डेड व नान ब्राण्डेड वस्तुओं का व्यापक संग्रह	चुनिंदा ब्राण्डड व नान ब्राण्डेड वस्तुएँ
7	प्रचार	संयुक्त रूप से	व्यक्तिगत रूप से
8	आकार	वृहद आकार	सीमित आकार
9	बाजार अनुभव	अल्पकालिक	दीर्घकालीक

स्रोत–एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट रिसर्च (वालूम–2, इशू–1, 2011)

उपरोक्त तालिका–4 से यह स्पष्ट है कि यदि इस क्षेत्र के उत्पादकता व क्षमता में बढ़ोत्तरी करनी है तो सरकार को ऐसे कार्यक्रम व नीतियों का निर्माण करना होगा, जिससे विदेशी निवेशकों के साथ–साथ स्थानोय खुदरा बाजार से जुड़े लोगों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हमें असंगठित खुदरा बाजार से जुड़े लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि इस क्षेत्र में एफ0डी0आई0 के बढ़ने से उनके लाभों में भी बढ़ोत्तरी होगी और उनके हितों को सुरक्षित रखा जायेगा। इण्डियन काउन्सिल फार रिसर्च इन इम्पैक्ट ऑफ आर्गनाइज्ड रिटेलिंग ऑन अनआर्गनाइज्ड सेक्टर इन्टरनेशनल इकोनामिक रिलेशन (ICRIER) के अनुसार **''यदि संगठित खुदरा बाजार का विस्तार आने वाले वर्षों में नहीं होता है तो असंगठित खुदरा बाजार भारतीय बाजार माँग को पूरा नहीं कर सकेगा**'' चेम्बर ऑफ ऑफ कामर्स एण्ड इण्डट्रीज ऑफ इण्डिया (एसोचेम) के अनुसार अगले कुछ वर्षों में भारत के रिटेल सेक्टर में 50 हजार नये रोजगार सृजित होंगे।

सुझाव एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र **''भारतीय खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश''** के विश्लेषण से कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, जिसे अध्ययन में सुझाव एवं निष्कर्ष के रूप में दिया जा रहा है–

1. सरकार को इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एक **'राष्ट्रीय कमीशन'** का गठन तुरन्त करना चाहिए, जो इस क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन, विदेशी प्रतियोगिता, रोजगार सृजन इत्यादि बातों का अध्ययन कर अपना सुझाव सरकार को दे।
2. इस बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभों का वितरण संगठित और असंगठित दोनों वर्गों को समान रूप से मिले, इस सम्बन्ध में सरकार को एक **'व्यापक राष्ट्रीय नीति'** की घोषणा करनी चाहिए।
3. सरकार का चाहिये कि इस क्षेत्र का विकास देश के सामाजिक–आर्थिक परिदृष्य में किसी प्रकार की हानि न पहुँचाये, इसके लिए एक **'रेगुलेटरी बोर्ड'** की स्थापना की जानी चाहिए, जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के हितों को सुरक्षित रख सके।
4. असंगठित खुदरा बाजार क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र, वित्तीय सहायता एवं कौशल तकनीकी का विकास करके विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने लायक बनाना होगा।
5. खुदरा क्षेत्र में एफ0डी0आई0 विभिन्न अवस्थाओं (Difference Phase) में लागू करना चाहिए। जैसा कि चीन ने किया।
6. अन्त में सरकार को देश के निर्माण क्षेत्र (s) के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि असंगठित खुदरा बाजार क्षेत्र में लगे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर समायोजित कर सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय खुदरा बाजार का भविष्य बहुत सुनहरा है। इस क्षेत्र का सुनियोजित विकास अर्थ–व्यवस्था पर घनात्मक प्रभाव डालेगा। परन्तु हमें अपनी सीमाएँ तय करनी पड़ेगी तभी हम विकास के साथ एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। हमें विकास के लाभों का वितरण ईमानदारी से इस क्षेत्र में लगे सभी वर्गों में वितरित करना होगा। तभी यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुकूलतम लाभ उठा सकेगा। इसमें सरकार की भूमिका और मंशा महत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, ए (2010) ''फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट इन इण्डिया रिटेल सेक्टर : स्ट्रेटजिक इशू एण्ड इन्प्लिकेशन'', वालूम–1 (।), पी0पी0–55–68

2. गर्ग, जी (2015) एन इकोनोमिक एनलसेस ऑफ एफ0डी0आई0 इन रिटेल सेक्टर इन इण्डिया, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन, 03 (12)
3. के0टी0 केर्न (2009) रिपोर्ट ऑन ''ग्रोथ अप्रच्यूनिटी फार ग्लोबल रिटेलर्स'' इन द ए0टी0 केर्न 2009 ग्लोबल रिटेल डवलपमेन्ट इण्डेक्स।
4. डौल्टी (2011) ''इण्डियन रिटेल मार्केट : इण्डैरेसिंग ए न्यू ट्रेजेक्ट्री'' सितम्बर 2005 से 2015
5. एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेन्ट रिसर्च (वालूम–2) इशू–1, 2011
6. फिक्की (2011) ''सेक्टर प्रोफाइल, दिसम्बर 2010 से 2020
7. मिड इयर इकोनोमिक एनेलसिस 2014–15, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेन्स गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया, पी0पी0–02
8. सेण्ट्रल स्टेटिक्स आफिस 2014
9. इण्डियाज इकोनोमिक ग्रोथ मे बिट चाईना बाई 2015 : गोल्डमैन साच, एशिया पल्स, फरवरी 07, 2005
10. इकोनोमिक सर्वे ऑफ इण्डिया 2014–15, गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया, 2014